राजस्थान समसामयिकी जनवरी , 2023

राजस्थान समसामयिकी जनवरी, 2023
(Current News from Daily News Papers)

News Paper of 1 January, 2023

- **राजस्थान रिफाइनरी का पेटकोक डोम भारत की 25 रिफाइनरियों में सबसे बड़ा; इससे रोजाना 200 मेगावाट बिजली बनेगी—**

राजस्थान के पचपदरा में निर्माणधीन राजस्थान रिफाइनरी का 125 डायामीटर गोलाई में 64 मीटर ऊंचा पेटकोक डोम बन रहा है, जिसमें 95,600 मीट्रिक टन पेटकोक भरा होगा। इस पेटकोक को बॉयलर में जलाकर प्रतिदिन 200 मेगावाट (लगभग 83 लाख यूनिट) बिजली का उत्पादन होगा।

राजस्थान रिफाइनरी में बन रहा पेटकोक डोम देश की 25 रिफाइनरियों में मौजूद डोम में सबसे बड़ा है।

गौरतलब है कि राजस्थान रिफाइनरी में भारत स्टेज यानी बीएस-6 ग्रेड का डीजल ही तैयार होगा, जिसमें सल्फर मात्र 10 पीपीएम होगी। सल्फर की मात्रा जामनगर रिफाइनरी के अलावा सभी में 15 पीपीएम से ज्यादा होती है।

- **राजस्थान सरकार ने मनरेगा संविदाकर्मियों के मानदेय में 5% की बढोत्तरी की—**

राजस्थान सरकार की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की घोषणा के तहत मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) के संविदाकर्मियों के वेतन में 5% की बढ़ोत्तरी की गई है। यह वृद्धि 1 नवम्बर, 2022 से की गई है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 बजट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों (जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है) के मानदेय में वृद्धि के लिए घोषणा की थी।

- **राज्य में बांसवाड़ा जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 'सक्षम' अभियान का संचालन हो रहा है—**

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जिला प्रशासन द्वारा सभी लोगों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 'सक्षम' अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कर पात्रता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

News Paper of 2 January, 2023

- **राजस्थान सचिवालय में ई-फाइल सिस्टम लागू किया गया—**

2 जनवरी, 2023 से राजस्थान शासन सचिवालय में स्मार्ट फंक्शनिंग ई-फाइल सिस्टम लागू कर दिया गया है। ई-फाइल सिस्टम लागू होने से अब 40 हजार से ज्यादा रूटीन फाइल-पत्रावली मैन्युअल के बजाय ऑनलाइन हो गई हैं।

ई-फाइल सिस्टम लागू होने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी तथा फाइलों के रूट से संबंधित पूर्ण जानकारी ऑनलाइन रहेगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय से पैंडिंग है।

ई-फाइल सिस्टम लागू होने से कागज की बचत भी होगी।

News Paper of 3 January, 2023

- **स्टेट हाइवेज पर भी नेशनल हाइवे की तर्ज पर फास्ट टेग से टोल टैक्स की वसूली होगी—**

हाल ही में जारी राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की घोषणानुसार अब प्रदेश के स्टेट हाइवेज पर भी एनएचएआई की तर्ज पर फास्ट टैग के जरिए टोल वसूल किया जाएगा।

इसकी शुरुआत जयपुर और सीकर में बने स्टेट हाइवे पर बने टोल प्लाजा से होगी। राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजन लाल जाटव हैं।

- **जयपुर के प्रतापनगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में 'बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेन्टर बनाया जा रहा है'—**

बड़े महानगरों की तर्ज पर अब जयपुर के प्रताप नगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में 'बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर' बनाया जा रहा है। यह लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार होगा।

गौरतलब है कि कैंसर के जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उनमें से कुछ मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, अब यहां राज्य के मरीज निःशुल्क ट्रांसप्लांट करा सकेंगे।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- **प्रदेश के पर्यटन स्थल हवाई मार्ग से जुड़ेंगे—**

हाल ही में राजस्थान सरकार के पर्यटन विकास निगम (RTDC) द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर जॉयराइड के माध्यम से हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना है। इसके तहत राजस्थान में धार्मिक तथा वाइल्ड लाइफ आदि से संबंधित पर्यटन स्थलों को जोड़कर 'टूरिज्म सर्किट' बनाए जाएंगे। हाल ही में जैसलमेर की सम ढाणी में 'हेलीकॉप्टर जॉयराइड' शुरू की गई है।

News Paper of 4 January, 2023

- **राष्ट्रपति का राजस्थान दौरा; राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया, आबूरोड में ब्रह्मकुमारीज के सम्मेलन का उद्घाटन किया—**

3 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रदेश के दौरे पर आई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर स्थित राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किया तथा एसजेवीएन लि. की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राजस्थान का इतिहास ही नारी की गरिमा और सशक्तिकरण का है। तथा महिला सशक्तिकरण और समानता में राजस्थान का बड़ा येगादान रहा है। बाल विवाह के खिलाफ 1938 में यहीं हरविलास शारदा ने कानून बनाया था, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है।

राजभवन स्थित संविधान पार्क के प्रमुख आकर्षण–

- गांधी जी की 10×12 फीट की चरखा चलाते गन मेटल की मूर्ति। देश में बापू की सबसे बड़ी पहली प्रतिमा होने का दावा।
- आन-बान-शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रिय घोड़े चेतक के साथ सफेद मार्बल की प्रतिमा।
- मोर स्तंभ भी खास आकर्षक है।
- राजभवन परिसर में 30 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ स्थापित किया गया है।
- संविधान पार्क में ऑडियो-वीडियो गाइड का भी प्रावधान किया गया है जिससे आगंतुक हेडफोन व अन्य स्क्रीन्स की मदद से संविधान संरचना के बारे में देख व सुन सकेंगे। दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा में दिए गए नेताओं के भाषणों को भी यहां सुना और देखा जा सकेगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए गए संविधान पार्क को सामान्य जन सप्ताह में दो दिन देख सकेंगे जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राजस्थान के दौरे के दौरान 3 जनवरी, 2023 को ही आबू रोड़ स्थित ब्रह्मकुमारीज संस्थान के शांतिवन में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के तहत 'आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय' सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- **राजस्थान में 'बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' लागू—**

हाल ही में राजस्थान में 'बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 लागू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के तहत प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे कराएगा। सर्वे का कार्य संभाग स्तर, जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इस नीति में बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था के साथ आश्रय उपलब्ध कराना तथा उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा सशक्तिकरण पर्याप्त रोजगार सर्जन के साथ प्रशिक्षण के अवसर सहित स्वरोजगार एवं सामाजिक हकों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

'बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' एक नजर में-

राजस्थान 'बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नीति में पेयजल एवं चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुरक्षा आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल और रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

News Paper of 5 January, 2023

- **राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय गाइड जम्बूरी का आगाज किया—**

4 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आगाज किया। जम्बूरी कार्यक्रम 4 जनवरी, 2023 से 10 जनवरी 2023 तक रखा गया। यह 7 दिवसीय जम्बूरी राजस्थान में 67 वर्ष बाद हो रही है।

राष्ट्रीय जम्बूरी में भारत के विभिन्न राज्यों सहित अन्य देशों से 37 हजार से अधिक स्काउड एवं गाइड आए। यहाँ के कार्यक्रमों के दौरान 'मिनी यंग इंडिया' की झलक देखने को मिली।

उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आजादी के 75वें वर्ष की देश की विकास गाथा की झलक भी देखने को मिली, इस दौरान

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

स्काउट-गाइड्स ने एक साथ जम्बूरी गीत गाया।

राष्ट्रीय जम्बूरी के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन स्थल पर राजस्थान सरकार की विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

News Paper of 6 January, 2023

- **डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया—**

डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 'मिशन पालनहार' 5 जनवरी, 2023 से 4 फरवरी, 2023 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत-

- विद्यालयों, आंगनबाड़ी और मां बाड़ी केन्द्रों पर सर्वे कर पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जा रहा है।
- प्रथम चरण 20 दिन तक चलाया गया जिसमें सर्वे कर पात्र बच्चों को चिह्नीकरण किया गया।
- द्वितीय चरण 27 जनवरी से 4 फरवरी के दौरान पात्रों को योजना से जोड़ने के लिए सर्वे के दौरान संकलित दस्तावेजों के माध्यम से ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करवाया जाना निश्चित किया।

गौरतलब है कि पालनहार योजना के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए उसके निकटतम रिश्तेदार या परिचित को पालनहार बनाया जाता है। बच्चों के साथ ही पालनहार को भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में वार्षिक सत्यापन मोबाइल एप से किया जाना प्रस्तावित—**

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वार्षिक सत्यापन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली मोबाइल की सुविधा शुरू किया जाना प्रस्तावित है। जिसका मोबाइल एप 26 जनवरी, 2023 तक प्रारम्भ होगा।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों को प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक होता है। भौतिक सत्यापन ना होने के अभाव में पेंशन का भुगतान रोका जाता है। प्रतिवर्ष यह कार्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ किया जाता है।
- वर्तमान में ई-मित्र केन्द्र पर बॉयो-मैट्रिक आधारित सत्यापन किया जाता है।
- मोबाइल एप से वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुविधाजनक हो जाती है।
- आधार पर उपलब्ध डाटा के माध्यम से पेंशनरों का फेस रिकॉग्नेशन प्रणाली के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- इस सुविधा से हर साल 94 लाख लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाने में सुविधा होगी।
- ई मित्र पर अथवा एसडीएम या बीडीओ कार्यालय जाकर अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने के स्थान पर घर बैठे मोबाइल एप पर अपना चेहरा सामने रखकर इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा।
- आधार कार्ड पर उपलब्ध डाटा से पेंशनर की पहचान होने के साथ ही पेंशनर की E-KYC की जाएगी, जिसमें पेंशनर का नाम, आयु आदि विवरण आधार पोर्टल से प्राप्त कर उसका पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से मिलान किया जाएगा।

गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर और जन आधार अथॉरिटी के सहयोग से यह प्रणाली विकसित की जा रही है।

News Paper of 7 January, 2023

- **मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया—**

6 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में जनजाति राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में स्पोर्ट्स स्कूल (खेल विद्यालय) संचालित करने की घोषणा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय खिलाड़ियों के लिए एक महीने के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के गांगड़तलाई किसान सम्मेलन को भी सम्बोधित किया।

News Paper of 8 January, 2023

- **संयुक्त युद्धाभ्यास 'वीर गार्जियन' में सुखोई-30 की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी शामिल—**

भारत और जापान की सेनाओं के मध्य पहली बार संयुक्त युद्धाभ्यास 'वीर गार्जियन' होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में 4 सुखोई फाइटर के दल में शामिल सुखोई-30 की पहली महिला पायलट स्कवॉड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी पहली बार किसी विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं।

- **जयपुर में ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोला जाना प्रस्तावित —**

राजस्थान सरकार की घोषणानुसार जयपुर में ₹ 100 करोड़ की

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

लागत से यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोला जाना प्रस्तावित है। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में बिल पेश किया जाएगा।

यह राज्य का पहला ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होगा, जो यूजी-पीजी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए अपना सिलेबस तैयार करेगा और डिग्री भी देगा। यह संस्थान यूनिवर्सिटी स्तर का होगा लेकिन किसी भी कॉलेज को सम्बद्धता नहीं दे सकेगा।

वर्तमान में बीकानेर व कोटा में टेक्नीकल यूनिवर्सिटी है।

- **चंबल नदी के तीनों बांध जवाहर सागर, कोटा बैराज व राणाप्रताप सागर से जीर्णोद्धार की विश्व बैंक द्वारा मंजूरी दी गई—**

हाल ही में चम्बल नदी पर निर्मित तीनों बांधों - राणाप्रताप सागर, कोटा बैराज व जवाहर सागर के ₹ 183 करोड़ में जीर्णोद्धार करने के प्रोजेक्ट को केन्द्रीय जल आयोग के बाद विश्व बैंक ने भी मंजूरी दे दी है। इसमें राणा प्रताप सागर के लिए 65.72 करोड़ रुपये में 4 स्लूज गेट व 17 बड़े गेट सहित कुल 21 गेटों को नई तकनीक से बनाया जाएगा। जवाहर सागर के 12 और कोटा बैराज के 19 गेटों को धातु चढ़ाकर नया किया जाएगा।

गौरतलब है कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत वर्ल्ड बैंक ने देशभर के 733 बड़े बांधों की संरक्षा-मरम्मत के लिए 11 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें राजस्थान का माही बांध (बांसवाड़ा) भी शामिल है।

- **राजस्थान के तीन शहरों में 5जी इंटरनेट सेवा शुरू—**

7 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के तीन शहरों में 5जी इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। यह सेवा रिलायंस जियो द्वारा जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में उपलब्ध होगी।

5जी सेवा सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जियो ग्लास और कम्यूनिटी क्लिनिक उत्पाद भी लॉन्च किए। कोटा, बीकानेर एवं अजमेर में भी 5जी सेवा मिलेगी।

- **जोधपुर में 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव शुरू—**

7 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव' का उद्घाटन कर शुभारंभ किया। यह उत्सव 'विकासशील राजस्थान-उद्यमशील राजस्थान' मुख्य थीम पर आधारित है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं तथा सुनहरा भविष्य है-

- राजस्थान में उद्योग सहित सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है। इससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का सुनहरा स्वरूप सामने आ रहा है।
- एमएसएमई एक्ट के तहत उद्योगों को रियायतें देने का क्रान्तिकारी काम किया है।
- प्रदेश में सीमित संसाधनों के बावजूद भी हस्तशिल्प क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है।
- निवेश सम्मेलन 'इन्वेस्ट राजस्थान' में 11 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू होना भी शुभ संकेत है।
- पूरे राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों का जाल बिछ रहा है। रिफाइनरी का काम हो रहा है। खजूर, अनार की खेती हो रही है।
- हर ब्लॉक में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है। इससे इकाइयां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि होगी।
- स्टार्टअप्स और आईटी से युवाओं को फायदा मिलेगा। दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर से व्यवसायियों को फायदा मिलेगा।
- आगामी समय में रोहट में बहुत बड़ा औद्योगिक परिक्षेत्र विकसित होगा।

- **'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' की तर्ज पर 'राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर' विकसित हो रहा है; शीघ्र शुरू होगा—**

जयपुर में 'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' की तर्ज पर 'राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर' विकसित हो रहा है। इस केन्द्र में कला-संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी गतिविधियां हो सकेंगी।

- इस सेंटर का अप्रैल 2013 में शिलान्यास किया गया था।
- इस सेंटर का आंतरिक निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर हो रहा है।
- इसमें 700 व्यक्तियों की क्षमता का सभागार, 500 क्षमता का कन्वेंशन सेंटर, 170-170 बैठक क्षमता के दो मिनी सभागार और 500 क्षमता का एग्जीबिशन एरिया बनेंगे।
- इसमें 3 कॉन्फ्रेंस हॉल, ई-लाइब्रेरी, 3 लेक्चर हॉल, 2 रेस्टोरेंट और डबल बेसमेंट पार्किंग की सुविधा मिलेगी।

News Paper of 9 January, 2023

- **'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत राजस्थान में 60 छोटे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा; प्रत्येक स्टेशन पर ₹15 करोड़ खर्च होंगे—**

हाल ही में भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे व कम यात्री भार वाले स्टेशनों को आधुनिक बनाने

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

की नीति तैयार की है। इसके तहत राजस्थान के जयपुर, अजमेर, बीकानेर व जोधपुर मंडल के 60 छोटे स्टेशनों का ₹ 900 करोड़ की लागत से मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर कायाकल्प किया जाएगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निम्न कार्य होंगे–

- प्रत्येक स्टेशन का मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
- प्लेटफॉर्म को लंबा किया जाएगा।
- ट्रेक गिट्टी रहित तैयार होंगे।
- इंटरनेट की सुविधा विकसित होगी।
- पार्किंग की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
- रोशनी, छाया व पेयजल की सुविधा पहले से बेहतर होगी।
- आरामदायक कुर्सियां लगाई जाएंगी।
- वेटिंग रूम बनाए जाएंगे।
- दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा की जाएगी।

● राजस्थान में 'राइट टू हेल्थ बिल' पास किया जाएगा—

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणानुसार राज्य में शीघ्र ही 'राइट टू हेल्थ बिल' पास किया जाएगा। इससे राज्य में चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

● राजस्थान की गर्ल्स बॉलीवॉल टीम ने 44वीं नेशनल-जूनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जीती—

जनवरी, 2023 में राजस्थान की बॉलीवॉल गर्ल्स टीम ने नई दिल्ली में आयोजित 44वीं नेशनल-जूनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जीती है।

राजस्थान की गर्ल्स टीम ने फाइनल में उत्तर प्रदेश को 3-1 से हराया।

बॉयज वर्ग में दिल्ली की टीम विजेता रही है। इसमें दिल्ली ने गुजरात को 3-1 से पराजित किया।

● देश का सबसे बड़ा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम कोटा में हुआ; वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 33,834 लाभार्थियों को 1579.56 करोड़ रुपये ऋण के चेक बांटकर एक कीर्तिमान कायम किया—

8 जनवरी, 2023 को कोटा में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में 33834 लाभार्थियों को 1579.56 करोड़ रुपये ऋण के चेक बांटकर एक कीर्तिमान कायम किया।

यह देश का सबसे बड़ा ऋण मेला माना जा रहा है। इस आउटरीच कार्यक्रम के एक ही आयोजन में लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई ऋण राशि की दृष्टि से यह देश का अब तक का सबसे बड़ा और सफल कार्यक्रम रहा।

लाभार्थियों में सब्जी, फल, फूल, चाय-नाश्ता तथा अन्य फुटकर सामग्री बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर लघु उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, पशुपालक, किसान, युवा आदि शामिल हैं।

इस दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की।

News Paper of 10 January, 2023

● गांधी लीगेसी टूर-2023; गांधीवादी विचारकों के दल ने राज्य सरकार के 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस' का भ्रमण किया—

9 जनवरी, 2023 को गांधी लीगेसी टूर-2023 के तहत भ्रमण के दौरान 19 गांधी विचारकों के एक दल ने राज्य सरकार के 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस का भ्रमण किया। देशी-विदेशी गांधीवादी विचारकों ने कहा कि 'राष्ट्र की परिकल्पना को बचाने के लिए महात्मा गांधी प्रासंगिक हैं, उनकी विचारधारा एवं सिद्धान्तों को आत्मसात् करना जरूरी है।'

● राजस्थान के उदयपुर के विकास पुरोहित सोशल मीडिया कंपनी मेटा इंडिया के ग्लोबल बिजनेस हेड बने—

हाल ही में टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा इंडिया ने उदयपुर के विकास पुरोहित को भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले ये टाटा ग्रुप के ई-कॉमर्स वेंचर क्लिक के सीईओ पद पर कार्यरत थे।

News Paper of 11 January, 2023

● 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी, 2023 को राजस्थान में—

4 जनवरी, 2023 को देश के सबसे बड़े स्काउट-गाइड महाकुंभ यानि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आगाज राजस्थान के पाली जिले के रोहट में हुआ। जम्बूरी कार्यक्रम 4 जनवरी, 2023 - 10 जनवरी, 2023 तक चला। राजस्थान को 66 वर्षों बाद जम्बूरी की मेजबानी मिली है।

4-10 जनवरी, 2023 तक चलने वाली इस 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन माननीया राष्ट्रपति श्रीमति द्रोपदी मुर्मू ने किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र रहे व अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत ने की।

उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का ध्वज फहराया और जम्बूरी परेड का अवलोकन किया।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

इस जम्बूरी में देश-विदेश के 35 हजार से अधिक सहभागियों ने भाग लिया। प्रतिदिन सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा एयर शो, विभिन्न खेल एवं एडवेंचर गतिविधियां, विकास प्रदर्शनी, फोक डांस, बैंड डिस्प्ले, पीजेंट शो, ग्लोबल विलेज एक्टिविटीज आदि शामिल रहीं। जिसमें जम्बूरी कार्यक्रम में 'मिनी यंग इंडिया' की झलक नजर आई।

18वीं राष्ट्रीय स्काउट-गाइड्स जम्बूरी का राजस्थान में होना एक मेजबान के रूप में राजस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का थीम गीत पाली जिले के अध्यापक दीपक जावा ने लिखा है।

जम्बूरी स्थल पर 'अपनी सेना को जानो' प्रोग्राम के तहत सेना की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें एआरओ, स्मॉल आर्म इक्विपमेंट, एल-70, जेडयू एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, स्ट्रेला 10 एम, एचएमपीए 1300 एमएम, सोल्टम 15-5 एमएम, सीएमटी, एएटी, बीएमपी सेकंड केज टी 90 टैंक और आर्मी टैंक का प्रदर्शन किया गया।

राष्ट्रीय जम्बूरी में विभिन्न गतिविधियों एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विविधता का अनूठा प्रदर्शन किया गया जिसमें झांकियों के माध्यम से स्थानीय संस्कृतियों का प्रदर्शन, राज्य प्रदर्शनी में विभिन्न इलाकों की कलाओं, रीति-रिवाजों, हस्तशिल्प, पहनावे आदि शामिल रहे।

राजस्थान को 66 वर्ष बाद राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी की मेजबानी मिली है, इस अवसर पर राजस्थान दिवस भी मनाया गया तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए।

10 जनवरी, 2023 को 7 दिवसीय 18वीं राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी का 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के साथ समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर रहे।

समापन के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना के साथ देश के कोने-कोने एवं विदेशों से आए स्काउट-गाइड जम्बूरी में सीखे, सेवा और समर्पण के उच्च आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश और जम्बूरी की स्मृतियों को लेकर वापिस लौटे।

जम्बूरी के दौरान स्काउट्स अवार्ड में राजस्थान सिरमौर रहा। समापन के अवसर पर स्टेट चीफ कमीश्नर निरंजन आर्य ने जम्बूरी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

विशेष- राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्डस में राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड राजस्थान ने अपने नाम किए। अतिथियों ने स्टेट चीफ कमिश्नर श्री निरंजन आर्य सहित स्काउट गाइड एवं अधिकारियों को अवार्ड दिए।

- **जन शिकायतों की समस्या के समाधान में राजस्थान देश में अव्वल रहा—**

हाल ही में राजस्थान ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान 'सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांवों की ओर-2022' के तहत दो श्रेणियों सेवा प्रदायगी (सर्विस डिलीवरी) एवं जन अभियोग निराकरण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

अभियान के दौरान राजस्थान ने देश में विस्तारित किए गए जन अभियोग के 53.8 लाख मामलों में से 23.36 लाख तथा सेवा प्रदायगी के 3.1 करोड़ मामलों में से 1.49 करोड़ प्रकरण निस्तारित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

सेवा प्रदायगी में अलवर जिला प्रथम रहा तथा जन अभियोग निराकरण में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा।

राजस्थान वर्ष 2011 में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लाने के साथ ही वर्ष 2012 में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लाने वाला प्रथम राज्य है।

- **18वीं राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी अवार्ड्स में राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला—**

राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड मिले।

News Paper of 12 January, 2023

- **जयपुर में हर महीने 100 भिखारियों को रोजगार दिलाया जाएगा—**

हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए भिखारियों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए है। इस क्रम में जयपुर जिला प्रशासन ने हर महीने रेस्क्यू किए गए 100 भिखारियों को रोजगार मुहैया करवाने की योजना बनाई है।

जयपुर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के अनुसार, जयपुर में अभियान का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में राज्य बजट में घोषणा की थी।

भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत 4 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन हुआ है।

जयपुर में कुल 390 भिखारियों को रेस्क्यू किया गया है।

अगले चरण में जिला प्रशासन रेस्क्यू किए गए भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण के बाद गोशालाओं, मंदिर प्रबंधन समिति

तथा अन्य कार्य स्थलों पर नियमित रोजगार मुहैया करवायेगा।

अभी तक 22 भिखारियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

अभियान के तहत भिखारियों के पुनर्वास के लिए 4 पुनर्वास केन्द्र चिन्हित किए गए हैं।

14 नवम्बर, 2022 से जयपुर शहर के मुख्य चौराहों पर दो सप्ताह तक सलाह एवं परामर्श कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें आमजन एवं भिखारियों से समझाइश की गई।

- **चिरंजीवी योजना में लाभार्थियों की मदद के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू होगी—**

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या नहीं आए और तुरंत समाधन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी चिरंजीवी योजना के लिए जल्द ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू करेगी। इसके लिए विभाग एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा।

यदि किसी लाभार्थी को योजना से संबंधित कोई भी समस्या होगी, तो वह उस नंबर पर मैसेज कर सकेगा।

मैसेज को तत्काल ही संबंधित को भेजकर लाभार्थी की समस्या का समाधान करवाया जाएगा।

News Paper of 13 January, 2023

- **पूर्व डीजीपी एम एल लाठर को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया—**

हाल ही में राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने पूर्व डीजीपी एम एल लाठर को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता के अधीन कार्य करेंगे। इनके पास 3 साल जिम्मेदारी रहेगी।

- **राजस्थान सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी और स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की—**

राजस्थान सरकार ने कृषि श्रेणी के नियमित और कटे हुए कनेक्शनों तथा अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है।

कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित कराने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की है। दोनों योजनाएं तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।

गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है।

- **83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन—**

11 जनवरी, 2023 को 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत राजस्थान विधानसभा में हुई। इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ तथा अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। यह दो दिवसीय सम्मेलन 11 व 12 जनवरी को आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ-साथ देशभर के विधानसभा और विधानपरिषद के स्पीकर शामिल हुए जिन्होंने G-20 से लेकर विधायिका और न्यायपालिका के सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर मंथन किया। राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का यह चौथा सम्मेलन है। इससे पूर्व 3 सम्मेलनों में-

- 23वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 14-16 अक्टूबर 1957 को
- 44वां सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1978 को तथा
- 76वां सम्मेलन 21-22 सितम्बर 2011 को हुआ था

ये सभी सम्मेलन जयपुर में हुए।

इस सम्मेलन में लोकसभा एवं राज्यसभा के स्पीकर राजस्थान से हैं ऐसा पहली बार हुआ है। जिन्होंने जी-20 से लेकर विधायिका और न्यायपालिका के सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर मंथन किया।

इस सम्मेलन में संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज, उनकी कमजोरियां, दायित्व पूरा नहीं करने और दूसरे के काम में दखलंदाजी पर विशेष चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 'लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।' उन्होंने सदनों में हंगामा व संसदीय कार्य में सुप्रीम कोर्ट के दखल पर गंभीर सवाल उठाए। इसी के साथ-साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने भी संसदीय कार्य में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई। पहले दिन सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष डॉ सी.पी. जोशी तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया।

इस सम्मेलन में संसद और विधानसभाओं को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने को लेकर भी विभिन्न सत्रों के दौरान चर्चा हुई।

12 जनवरी, 2023 को इस 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन हुआ इस दौरान 9 संकल्प लिए गए/प्रस्ताव पारित किए गए।

- पहला संकल्प है कि भारत में आयोजित होने वाले जी-

20 राष्ट्रों के समूह और संसद-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

- दूसरा संकल्प है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था रखी जाए। इसके लिए राज्य के सभी अंगों को संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने का आह्वान किया गया।
- तीसरा संकल्प विधायी निकायों की कार्यवाही में सदस्यों की अधिक भागीदारी और आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं बनाने के लिए पारित किया गया। इसके तहत असंसदीय आचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियम प्रक्रियाओं में आचार संहिता को शामिल करने पर सहमति बनी।
- चौथा संकल्प है कि सभी राजनैतिक दल विधान मंडलों की सभाओं में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने का निर्णय लें।
- पांचवां संकल्प विधानमंडलों में समिति प्रणाली को सशक्त करने और कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा की सीमा बढ़ाने के लिए सभी विधायी निकायों से सार्थक कदम उठाने का आह्वान करते हुए लिया गया।
- छठा संकल्प संघ और राज्य विधान मंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के संबंध में पारित कर लोक सभा अध्यक्ष को संबंधित राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया।
- सातवां संकल्प भारत में सभी विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ने हेतु कदम उठाने से संबंधित है।
- आठवें संकल्प के रूप में हर वर्ष उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार दिया जाएगा।
- नौवां संकल्प समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए विशेष संभव प्रयास करने के लिए लिया गया।

सम्मेलन के समापन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने संबोधित किया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने समापन समारोह में विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता की सहमति देने की मांग की, जिसे सीएम अशोक गहलोत ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी। अब विधानसभा को अपने वित्तीय खर्चों के लिए सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। विधानसभा का सालाना बजट 100 करोड़ रुपये होता है, लेकिन मंजूर वित्त विभाग करता है। ऐसे प्रस्ताव पर सहमति जताने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने राजस्थान विधानसभा में हुए नवाचारों पर विस्तार से जानकारी दी तथा देशभर से आए पीठासीन अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधायी समितियों के कार्य को और बेहतर बनाए जाने पर बल दिया।

News Paper of 14 January, 2023

- **राजस्थान हाईकोर्ट को 9 नए न्यायाधीश मिले, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी की; 6 न्यायिक अधिकारी एवं 3 अधिवक्ता कोटे से; अधिवक्ता कोटे से पहले दंपति—**

13 जनवरी, 2022 को केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजस्थान हाइकोर्ट के लिए 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। नवनियुक्त न्यायाधीशों में 3 अधिवक्ता कोटे से तथा 6 न्यायिक अधिकारी हैं। नवनियुक्त 9 न्यायाधीश निम्न हैं-

1. गणेश राम मीणा- अधिवक्ता कोटे से SC व ST वर्ग में राजस्थान के पहले न्यायाधीश
2. अनिल उपमन - अधिवक्ता कोटे से, हाइकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं।
3. नुपुर भाटी - अधिवक्ता कोटे से पहले दम्पती (पति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी पहले से न्यायाधीश हैं।)
4. राजेन्द्र प्रकाश सोनी - वर्तमान में कोटा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर कार्यरत हैं।
5. अशोक कुमार जैन - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव। राज्य विधि सेवा प्राधि. सदस्य सचिव भी रहे।
6. भुवन गोयल - वर्तमान में प्रमुख विधि सचिव हैं और मुख्य न्यायाधीश के प्रधान निजी सचिव भी रह चुके हैं।
7. प्रवीर भटनागर - वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में निदेशक (विधि) हैं।
8. योगेन्द्र कुमार पुरोहित - वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलवर हैं।
9. आशुतोष कुमार - वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर मेट्रो प्रथम हैं।

गौरतलब है कि वर्तमान में राजस्थान हाइकोर्ट में न्यायाधीश के 50 पद हैं, जिनमें वर्तमान में 26 कार्यरत हैं व 24 पद रिक्त हैं।

- **नगरीय विकास विभाग ने 5जी के तहत टावर और टेलीग्राफ लाइन लाइसेंस के नए प्रावधान लागू किए—**

13 जनवरी, 2023 को नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान के

3 बड़े शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर) में 5जी शुरू करने के बाद अब 5जी के तहत टावर और टेलीग्राफ लाइन लाइसेंस के नए प्रावधान लागू किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब राजस्थान में-

- अंडरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन का लाइसेंस शुल्क 1000 रु. प्रति किमी. है।
- जमीन के ऊपर 'ओवरलाइन' 1000 रु. प्रति किमी. के साथ 1000 रु. प्रति पोल व 10000 रु. प्रति टावर लगाने का शुल्क लगेगा।
- अंडरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन का वार्षिक शुल्क - जिला मुख्यालय पर 2000 रु. प्रति मेनहोल टाउन में 1000 रू. प्रति मेनहोल।
- रूफ टॉप या ग्राउंड टावर वार्षिक शुल्क 10000 रू.
- सरकारी जमीन पर मोबाइल टावर वार्षिक शुल्क - नगर परिषद या जेडीए क्षेत्र में 2000 रु., निगम में 1500 रु., नगर पालिका में 1000 रु. और पंचायतों में 500 रुपए।
- छोटे सेल, टेलीग्राफ लाइन के लिए पोल स्थापना का शुल्क 1000 रु.
- टेलीग्राफ लाइन के लिए स्माल फर्नीचर प्रयोग का शुल्क 1000 रु.।
- ऑप्टिकाल फाइबर केबल बिछाने के लिए आवेदन फीस 1000 रु.।
- सड़क या सरकारी सम्पत्ति क्षेत्र में मोबाइल टावर के लिए आवेदन फीस 10000 रु.।

अब निजी भवन, इमारत पर मोबाइल टावर व अन्य उपकरण लगाने से पहले जनता की आपत्ति-सुझाव लेने की बंदिश हटा दी गई है। अब मोबाइल ऑपरेटर को संबंधित ऑथारिटी से अनुमति भी नहीं लेनी होगी, केवल सूचना देनी होगी।

अभी तक यह व्यवस्था थी-

मोबाइल टावर लगाने से पहले ऑपरेटर पहले संबंधित अथॉरिटी में आवेदन करता है और फिर अथॉरिटी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करती है। लोगों से 15 दिन में आपत्ति, सुझाव मांगे जाते हैं। निर्धारित प्रावधान की पालना नहीं होने और जनता का विरोध होने पर वहाँ टावर लगाने की अनुमति नहीं दी जाती।

● राजस्थान अंधता नियंत्रण लागू करने वाला पहला राज्य बना; सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर, आई बैंक खुलेंगे—

13 जनवरी, 2023 को राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार 'राइट टू साइट विजन' के उद्देश्य से राज्य में अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। राजस्थान 'अंधता नियंत्रण नीति' लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति का उद्देश्य 'राइट टू साइट विजन' रखा गया है। वर्तमान में राज्य में 3 लाख से अधिक लोग दृष्टिबाधित हैं। जिनके जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से यह नीति लाई गई है। इस नीति के तहत-

- देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1% थी, जिसे 'राइट टू साइट विजन पॉलिसी' की मदद से 0.3% तक लाने की दिशा में प्रयास होंगे।
- नीति के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई-बैंक संचालित होंगे।
- निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पतालों एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर नेत्रदान के लिए मुहिम चलाई जाएगी।
- नेत्र विशेषज्ञों, मेडिकल विद्यार्थियों, नेत्रदान के लिए परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस नीति के तहत राज्य सरकार निजी संस्थाओं को साथ लेकर व्यापक स्तर पर नेत्रदान के लिए मुहिम चलाएगी तथा अंधता नियंत्रण संबंधी जन-जागरुकता और विभिन्न तकनीकी सुधार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

● बीकानेर में 29वां अन्तर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव शुरू—

13 जनवरी, 2023 को बीकानेर कार्निवाल के साथ 29वां 'अन्तर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव' प्रारम्भ हुआ। इसकी शुरूआत मश्क वादन से हुई।

29वां बीकानेर कार्निवाल एक नजर में-

- कार्निवाल की शुरुआत मश्क वादन से हुई। इस दौरान पारम्परिक वेशभूषा में सजे-धजे रौबीलों ने राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति को साकार किया।
- बीएसएफ के ऊँटों का दस्ता विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा।
- कार्निवल में टेबूलो थीम के साथ फेस्टिवल के मस्कट 'फेलिक्स' को दर्शकों ने विशेष पसंद किया।
- इस दल में विंटेज कारें और रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलें शामिल हुईं। इन पर पारम्परिक वेशभूषा में सजकर बैठे विदेशी पर्यटकों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया।
- स्कूली विद्यार्थियों ने डोरेमोन, छोटा भीम, नोबिता जैसे कार्टून पात्रों का रूप धर बच्चों का मनोरंजन किया।
- कार्निवाल में कच्छी घोड़ी नृत्य और मयूर नृत्य की

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

प्रस्तुतियां शमिल रहीं। बहुरुपियों ने विभिन्न देवताओं, चार्ली चैपलिन, मोटू-पतलू, रावण आदि का रूप धरा।

- उत्सव के पहले दिन के दौरान एक हजार मीटर लम्बे साफे का प्रदर्शन किया गया।
- लोक कलाकारों ने चंग की थाप और सहरिया जनजाति के नृत्य प्रस्तुत किए।
- उत्सव के दौरान पंजाब के भांगड़ा-गिद्दा, जम्मू के रउफ, गुजरात के राठवा, हरियाणा के घूमर फोग, पुरुलिया के छउ तथा महाराष्ट्र के सौंगी मुखौटा नृत्य के कलाकारों ने देश की विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन कर विविधता में एकता का संदेश दिया।

● पुलिस विभाग के कार्यालयों का कामकाज पेपरलेस होगा—

पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के निर्देशानुसार आगामी समय में पुलिस विभाग का कामकाज भी पेपरलेस होगा। इस हेतु ई-फाइल मॉड्यूल अपनाने के निर्देश दिए गए। पेपरलेस कामकाल लागू करने के तहत पुलिस मुख्यालयों की शाखाओं तथा उनके समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई-फाइल मॉड्यूल लागू किया जाएगा। 30 जनवरी, 2023 से फाइल संधारण का काम राजकाज एप्लीकेशन के ई-फाइल मॉड्यूल से कार्य योजना अनुसार किया जाएगा।

ई-फाइल मॉड्यूल से निम्न फायदे होंगे-

- ई-फाइल मॉड्यूल से कार्य में पारदर्शिता आएगी। इससे पत्रावलियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। साथ ही किसी अधिकारी और कार्मिक के राजकीय यात्रा पर होने पर भी राज कार्य का समयबद्ध संपादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। डाक का संधारण और अवकाश संबंधित कार्य भी अनिवार्य रूप से राजकाज से ही किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा, पासपोर्ट, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, कार्यमुक्ति से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्य भी राजकाज के माध्यम से ही होंगे।
- 30 जनवरी, 2023 से फाइल संधारण का काम राजकाज एप्लीकेशन के ई-फाइल मॉड्यूल से कार्य योजना अनुसार किया जाएगा।
- स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआबी) को राजकाज क्रियान्वयन के लिए स्टेट नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। पुलिस के सभी कार्यालयों में ई-फाइल के लिए आरपीएस स्तर के नोडल अधिकारी और उनके अधीन सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
- एससीआरबी द्वारा संबंधित शाखा कार्यालयों को ई-फाइल का विस्तृत प्रस्तुतिकरण और प्रशिक्षण दिया जाकर इसे लागू करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। अब नई फाइल ई-फाइल मॉड्यूल द्वारा ही खोली जाएगी तथा पुरानी फाइलों को पूर्ण स्कैन कर प्राथमिकता से ई-फाइल मॉड्यूल पर लाया जाएगा।

News Paper of 15 January, 2023

● राजस्थान में खारे पानी से भी ग्रीन हइड्रोजन बनेगी—

राजस्थान में खारे (लवणीय) पानी से भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में खारे पानी के ब्लॉक व झीलें पर्याप्त मात्रा में हैं, जिससे उन स्थानों पर भू-जल दोहन भी नहीं हो रहा है। सरकार ने इस खारे पानी को उपयोगी बनाने के लिए इससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने हेतु ड्राफ्ट तैयार किया है। जिसे मंजूरी मिलते ही इसे शुरू किया जाएगा।

हाइड्रोजन उत्पादन के लिए मीठे व खारे दोनों तरह का पानी उपयोगी है। राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां खारे पानी का उपयोग किया जाएगा। दो किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए 18 लीटर पानी की जरूरत होगी।

इस तरह ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी-

बिजली जब पानी से होकर गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल ज्यादातर इण्डस्ट्रीज में होता है। यदि हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली अक्षय ऊर्जा से ले रहे हैं तो इससे प्रदूषण नहीं होता। इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है।

ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग पेट्रोलियम, स्टील प्लांट, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, परिवहन व विमानन क्षेत्र की इंडस्ट्रीज में होगा।

News Paper of 16 January, 2023

● राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों में गोशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की; प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में गोशाला और पशु आश्रय स्थल बनेंगे—

15 जनवरी, 2022 को राजस्थान सरकार ने राज्य की 1500 ग्राम पंचायतों में गोशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। प्रथम चरण में 1500 गोशाला एवं पशु आश्रय निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग ₹ 1377 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है।

- योजना के अंतर्गत, जिन ग्राम पंचायतों में गोशाला और पशु आश्रय स्थलों का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी (ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्था) उपलब्ध होगी, वहाँ प्राथमिकता से एक-एक करोड़ रुपये तक की राशि से गोशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 एवं 2023-24 में

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 90 प्रतिशत और कार्यकारी एजेंसी 10 प्रतिशत राशि वहन करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा स्थलों के निर्माण एवं संचालन के लिए वर्ष 2022-23 में 183.60 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2023-24 के लिए 1193.40 करोड़ रुपये सहित कुल 1377 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

- इससे आवारा एवं निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थाई आश्रय मिल सकेगा। साथ ही, आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिल सकेगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में ग्राम पंचायतों में गोशाला और पशु आश्रय स्थलों का संचालन किए जाने की घोषणा की गई थी।

- **राजस्थान सरकार द्वारा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के प्रारूप का अनुमोदन किया गया—**

हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 'उत्तर मैंट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस प्रारूप के तहत योजना में 2.50 लाख रुपये तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले मिरासी (ढाढ़ी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र 5000 से 20000 रु. तक छात्रवृत्ति मिलेगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्यों की घोषणा की थी।

News Paper of 17 January, 2023

- **राजभवन के संविधान पार्क में आमजन सप्ताह में दो दिन शुक्रवार व शनिवार को नि:शुल्क भ्रमण कर सकेंगे—**

राजभवन में निर्मित संविधान पार्क अब जनसामान्य के लिए भी खुलेगा। यहां सप्ताह में दो दिन शुक्रवार एवं शनिवार को आमजन को नि:शुल्क प्रवेश मिल सकेगा।

राजस्थान के राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यान आम लोगों के भ्रमण के लिए खुला रहेगा। सप्ताह में दो दिन शुक्रवार और शनिवार को आम दर्शक इसमें भ्रमण कर सकेंगे।

16 जनवरी, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क के भ्रमण के लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किया जिसका लिंक निम्न है-

www.rajbhawan.rajasthan.gov.in/content/rajbhawan/en/constitution-park-raj-bhawan.html

संविधान पार्क एक नजर में-

- इसमें संविधान निर्माण और उसके लागू होने की ऐतिहासिक यात्रा को विभिन्न कला-रूपों में संजोया गया है।
- संविधान पार्क मूल लिखित संविधान पर उकेरी प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियों का भी मूर्त रूप है।
- आमजन के लिए खुलने से अधिकाधिक लोग संविधान से जुड़ी संस्कृति से प्रत्यक्ष जुड़ सकेंगे।
- कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ऑनलाइन विजिटर बुकिंग में माध्यम से पंजीकरण करवाकर संविधान पार्क का अवलोकन कर सकता है।
- संविधान पार्क के अवलोकन से विद्यार्थियों और आमजन को संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों और इसकी मूल भावना को जानने-समझने का अवसर मिल सकेगा।
- इच्छुक दर्शक अपना नाम, आधार नंबर, फोटो, मोबाइल नम्बर आदि जानकारी अपलोड कर उद्यान भ्रमण के लिए स्लॉट बुक करवा सकते हैं।
- विद्यार्थी और संस्थाएं भी सामूहिक भ्रमण के लिए बुकिंग करवा सकेंगे।

News Paper of 18 January, 2023

- **हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक मुख्यालयों एवं जिला स्तर पर एक-एक खिलौना बैंक की स्थापनी की गई है। इन खिलौना बैंकों से एकत्रित खिलौना किटों का आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए वितरण किया गया।**
- **राजस्थान में पशुधन बीमा योजना पुन: शुरू की गई; एक परिवार में अधिकतम 5 पशुओं का बीमा होगा—**

राजस्थान में पशुपालकों को संबल प्रदान करने के लिए 5 वर्ष बाद 'पशुधन बीमा योजना' फिर से शुरू की गई है। केन्द्र सरकार ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत 'पशुधन बीमा योजना' पुन: शुरू की है।

इसमें एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाएगा। तथा बीमा की प्रीमियम दरों पर एससी, एसटी और बीपीएल पशुपालकों को 70 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य संवर्ग के पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से देय होगा।

- **बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए बनाया गया—**

17 जनवरी, 2023 को आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवा में राजस्थान काडर के अधिकारी रहे पंकज सिंह को डिप्टी एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार) बनाया गया है। इससे पहले वे एडीजी ट्रेफिक पद पर भी रह चुके हैं। हाल ही में वे बीएसएफ डीजी पद से रिटयर हुए हैं। वे राजस्थान

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

में एडीजी क्राइम और एडीजी यातायात पद पर भी रह चुके हैं।

- **राजस्थान सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 10 फरवरी, 2023 को पेश होगा—**

राजस्थान सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 10 फरवरी, 2023 को पेश होगा। यह बजट वर्तमान सरकार का अंतरिम बजट होगा। यह बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा।

News Paper of 19 January, 2023

- **देवेन्द्र सिंह बुटाटी राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग में सदस्य के रूप में नियुक्त हुए—**

हाल ही में कांग्रेस नेता देवेन्द्र सिंह बुटाटी को राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

- **जयपुर के जामडोली में दिव्यांगजनों के लिए प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित होगा; भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुए—**

राजस्थान के दिव्यांग जनों को विभिन्न सेवाएं एव सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर के जामडोली में स्थापित किया जाएगा। इसके तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच समझौता-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रमुख तथ्य-

- भारत सरकार कंपोजिट रीजनल सेंटर का संचालन अस्थाई स्थान पर करेगी।
- राज्य सरकार स्थाई भवन के लिए भूमि उपलब्ध करवाएगी।
- भारत सरकार द्वारा केन्द्र के भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
- सेंटर के संचालन से राज्य के दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। यहां दिव्यांगजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण की सुविधा होगी।
- दिव्यांगजनों को फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थैरेपी इत्यादि की सविधाएं भी नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली हैं।

- **राज्य सरकार कस्टम हायरिंग केन्द्रों पर 2 वर्ष में 1500 ड्रोन उपलब्ध करवाएगी—**

18 जनवरी, 2023 को कृषि विभाग की ओर से जयपुर जिले के जोशीवास गांव में किसानों के सामने राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का सजीव प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में कस्टम हायरिंग केन्द्रों पर 2 वर्षों में 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

- विभाग की योजना के अनुसार, ऐसे कृषक जो सीमित आय के कारण महंगे कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं, कस्टम हायरिंग केन्द्रों से यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- किसानों को कम लागत एवं कम समय में खेतों में रसायन के छिड़काव के लिए सक्षम बनाने के क्रम में इन केन्द्रों से ड्रोन भी किराए पर उपलब्ध होंगे।
- ड्रोन उपकरणों के लिए लागत का 40 एवं अधिकतम 4 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध होगा। किसानों के खेतों पर ड्रोन प्रदर्शन के लिए अधिकतम 6 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा।
- सभी 33 जिलों में एक साथ ड्रोन के माध्यम से रसायनों के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया।
- किसानों को नई तकनीक के उपयोग के प्रति जागरुक करने के लिए हर जिले में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन से छिड़काव का प्रदर्शन हुआ।
- प्रथम चरण में नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग होगा।
- राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं।

News Paper of 21 January, 2023

- **जोधपुर में तैनात स्वदेशी हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' कर्तव्यपथ पर नेतृत्व करेगा; एयरफोर्स के 45 विमान, 1 नेवी, आर्मी के 4 हेलिकॉप्टर हिस्सा लेंगे—**

जोधपुर में तैनात स्वदेशी कॉम्बेट हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्यपथ (पूर्व में राजपथ) पर भारतीय वायु सेना के फ्लाई पास्ट के नेतृत्व में पांच हेलिकॉप्टर को लीड करेगा। इनमें अपाचे और ध्रुव हेलिकॉप्टर के साथ एरो फार्मेशन बनाएंगे। स्वदेशी अवाक्स नेत्र फार्मेशन खास होगी। स्वदेशी अवाक्स के साथ 4 राफेल जोधपुर से उड़ान भरकर बीस सैकेंड के लिए एरो बनाकर 1000 फीट की ऊँचाई से कर्तव्यपथ से गुजरेंगे। 3 सुखोई 30 एमकेआई जोधपुर से उड़कर कर्तव्यपथ पर पहुँचेंगे और विक फॉर्मेशन में त्रिशूल बनाते हुए बिखर जाएंगे।

- **शासन सचिवालय में नया कार्यालय भवन बनाने के लिए ₹273.25 करोड़ की राशि मंजूर—**

जनवरी, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा शासन सचिवालय परिसर में नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए 273.25 करोड़ की राशि मंजूर की गई। नए भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- **राजस्थान में निवासरत 571 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी किए गए—**

20 जनवरी, 2022 को राजस्थान में लंबे समय से निवास कर रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन भारतीय नागरिकता पोर्टल के माध्यम से कुल 571 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

ये पाक विस्थापित नागरिक राजस्थान के विभिन्न जिलों में निवास कर रहे हैं। जनवरी से दिसम्बर 2022 की अवधि में कुल 1343 पाक विस्थापितों को राज्य में स्थायी वास (लाँग टर्म वीजा) की अनुमति दी गई।

News Paper of 22 January, 2023

- **राणाप्रताप सागर पन बिजलीघर की तीसरी यूनिट से भी बिजली उत्पादन शुरू हुआ—**

21 जनवरी, 2023 को राणा प्रताप सागर बांध (रावतभाटा) पर बने हाइडल बिजलीघर की 43 मेगावाट की एक और इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। पूर्ण क्षमता से संचालित होने पर इस इकाई से 10.32 लाख यूनिट/प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो सकेगा।

43-43 मेगावाट की कुल चार इकाइयों में से तीन इकाइयों में विद्युत उत्पादन हो रहा है। यहां बिजली उत्पादन लागत 25 से 30 पैसे प्रति यूनिट ही आता है।

गौरतलब है कि 14 सितम्बर 2019 को चम्बल नदी में अत्यधिक पानी की आवक से राणाप्रताप सागर पन बिजली घर की चारों इकाइयां पूरी तरह से जलमग्न हो गई थीं। इसके बाद पहली यूनिट दिसम्बर 2021 और दूसरी यूनिट जून, 2022 में शुरू हुई। अब तीसरी यूनिट भी शुरू की गई है।

वर्ष 1968 में राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझा चंबल घाटी परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध पर 172 मेगावाट (43 मेगावाट की 4 यूनिट) क्षमता का हाइडल बिजलीघर बनाया गया।

News Paper of 25 January, 2023

- **1 अप्रैल, 2023 से सड़क पर 15 साल से अधिक पुराने वाहन नहीं चलेंगे; सड़क व परिवहन मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया—**

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर केन्द्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से अधिक सभी पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाई है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से राज्य में कोई भी ऐसा पुराना सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर स्क्रैप कर दिया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार पुराने वाहनों का निपटारा मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग के कार्य) नियम, 2021 के मुताबिक स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों पर जमा किया जाएगा। वर्ष 2008 से पहले पंजीकृत सभी वाहन 1 अप्रैल, 2023 से रद्द हो जाएंगे। इसमें राज्य सरकार के मोटर गैराज विभाग एवं अन्य विभागों, रोडवेज नगर निगम, नगर पालिका, पीएसयू आदि के वाहनों के पंजीकरण रद्द किए जाएंगे।

गौरतलब है कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का नियम रक्षा, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा। अधिसूचना में इन्हें विशेष छूट दी गई है। इन्हें स्पेशल पर्पस व्हीकल माना गया है।

- **मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए 25 हाइटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया—**

24 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस के लिए 25 हाइटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इंटरसेप्टर वाहन डिजिटल तकनीक से लैस हैं तथा वाहनों की गति मापने एवं नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम हैं। इन पर सड़क सुरक्षा कोष से 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

इन सड़क इंटरसेप्टर वाहन में उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक और कैमरा से एक किलोमीटर दूरी से वाहनों की गति मापी जा सकती है।

इंटरसेप्टर की स्पीड लेजर गन दिन में 250 मीटर और रात में 100 मीटर दूरी से वाहनों की नंबर प्लेट पहचान सकती है।

इंटरसेप्टर वाहन एआई तकनीक से ई-चालान जारी कर सकता है।

News Paper of 26 January, 2023

- **25 जनवरी 2023 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह—**

25 जनवरी, 2023 को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने निर्वाचन संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 29 राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों का सम्मान किया। राजस्थान को निर्वाचन क्षेत्र में निम्न उपलब्धियाँ हासिल हुईं-

- मतदाताओं के नए पंजीकरण ऑनलाइन प्रक्रिया से करने में राजस्थान देश में अव्वल है।
- राजस्थान में निर्वाचन साक्षरता क्लबों की संख्या बढ़कर 71 हजार हो गई है।

- मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में 12 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं।

राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हैं।

- **राजस्थान के 8 साहित्यकारों को 'अमृत सम्मान' देने की घोषणा—**

24 जनवरी, 2023 को राजस्थान के 8 रचनाधर्मियों/साहित्यकारों को वर्ष 2022-23 का 'अमृत सम्मान' के लिए 75 वर्ष से अधिक उम्र के साहित्यकारों का चयन किया गया है। ये पुरस्कार 28 जनवरी को प्रदान किए गए।

2022-23 के लिए अमृत सम्मान से सम्मानित साहित्यकार निम्न हैं-

- डॉ. सुलोचना रांगेय राघव (जयपुर)
- श्रीमती पुष्पा शरद देवड़ा (जयपुर)
- डॉ. कल्याण प्रसाद वर्मा (जयपुर)
- श्री ग्यारसी लाल सेन (झालावाड़)
- श्री लक्ष्मी नारायण रंगा (बीकानेर)
- श्री सरल विशारद (बीकानेर)
- श्री शिव कुमार शर्मा मधुप (चुरू)
- श्रीमती भारती भावसार (बांसवाड़ा)

गौरतलब है कि अमृत सम्मान हिन्दी भाषा, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, साक्षरता, पत्रकारिता आदि की सेवा करने वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के साहित्यकार, जिनको इससे पहले अकादमी का कोई भी सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, दिया जाता है। इसमें सम्मान राशि के रूप में 31 हजार रुपये देय हैं।

'अमृत सम्मान' के लिए चयनित साहित्यकार पूर्व में अलग-अलग संस्थाओं से भी सम्मानित हैं।

News Paper of 28 January, 2023

- **राज्य सरकार की ओर से 'राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2023' तथा 'द राजस्थान इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एवं रेगुलेशन) बिल, 2023 प्रस्तावित—**

राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी समय में जल्द ही कानून लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से-

'राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023' तथा 'द राजस्थान इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल, 2023' प्रस्तावित किए गए हैं।

इन विधेयकों का उद्देश्य व्यवस्था को दुरुस्त करना एवं मिलजुलकर समस्याओं के समाधन के प्रयास करना है। क्योंकि राज्य जैसे-जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विद्यार्थियों, अभिभावकों और संस्थानों को अधिक व्यवस्थित वातावरण की आवश्यकता महसूस हो रही है।

- **जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 फरवरी, 2023 से 'साइलेंट एयरपोर्ट'—**

जयपुर एयरपोर्ट को 1 फरवरी, 2023 से साइलेंट एयरपोर्ट बनाया है, इसके तहत यहां अब यात्रियों को उनकी फ्लाइट के आवागमन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग से लेकर अन्य सभी तरह के अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देंगे। एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब एलईडी पर दर्ज जानकारियों के हिसाब से ही यात्रा करनी होगी।

गौरतलब है कि अभी तक दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ समेत बड़े एयरपोर्ट साइलेंट एयरपोर्ट की श्रेणी में आते हैं, अब जयपुर एयरपोर्ट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर वर्तमान में 55 से ज्यादा फ्लाइट संचालित हो रही हैं तथा यात्रीभार भी लगभग 15000 तक है।

- **बालगोपाल योजना के तहत स्कूलों में दूध अब बुधवार व शुक्रवार दिवसों पर मिलेगा—**

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। पूर्व में इसके लिए सप्ताह के मंगलवार व शुक्रवार के दिन निर्धारित थे लेकिन अब इसमें बदलाव कर बुधवार व शुक्रवार कर दिया गया है।

News Paper of 29 January, 2023

- **ईको टूरिज्म बढ़ाने के लिए दौसा जिले में नीलकंठ बॉयोडायवर्स फॉरेस्ट तथा खान भांकरी ईकोपार्क का विकास होगा—**

वर्ष 2022-23 के बजट के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधा संबंधी कार्य कराए जाने की घोषणा की गई थी, इसके तहत दौसा जिले में नीलकंठ बायोडायवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी ईको पार्क का विकास होगा। इनके लिए 3 करोड़ रुपए (प्रत्येक के लिए 1.5-1.5 करोड़ रुपए) की मंजूरी दी गई है।

नीलकंठ बायोडायवर्स फॉरेस्ट में वन्यजीव संरक्षण, पर्यटक सुविधा और पर्यावरण जागरुकता के कार्य किए जाएंगे। पर्यटक सुविधाओं में वॉकिंग ट्रेक, ईको हट, पानी सुविधा, कुर्सियां, वॉच टावर, एंट्री गेट, साइनेज, वन्यजीव संरक्षण में तलाई, एनिकट, पौधरोपण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे।

खान भांकरी ईको पार्क में वॉकिंग ट्रेक, गार्डन वर्क, फेंसिंग, दीवार, कार्यालय भवन सहित विभिन्न कार्य होंगे। यहां छोटा

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

तालाब है जिसमें नौकायन भी शुरू की जा सकती है। तथा यहां पहाड़ी के चारों तरफ लगभग 4.5 किलोमीटर में वॉकिंग ट्रेक प्रस्तावित है। इसके साथ ही रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण एवं तलाई की खुदाई कर सौंदर्यकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

- **15 से 17 फरवरी तक 'जालोर महोत्सव' का आयोजन होगा—**

जालोर जिला प्रशासन द्वारा जालोर जिले में 15 से 17 फरवरी तक 'जालोर महात्सव' का आयोजन होगा। 'जालोर महोत्सव' में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, पुस्तक मेला सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

- **20 से 22 मार्च, 2023 तक जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा—**

20-22 मार्च, 2023 तक जोधपुर के ईपीसीएच सेंटर बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला (इंटरनेशनल एक्सपो) आयोजित किया जायेगा।

एक्सपो में जोधपुर से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद फर्नीचर के साथ ही कृषि एवं विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण उद्योगों, इंजीनियरिंग उत्पाद, स्टील आदि का भी प्रदर्शन किया जाएगा।

आयोजन के लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित एशिया के विभिन्न देशों के भारतीय दूतावास एवं उच्चायुक्तों के माध्यम से विदेशी क्रेताओं से सम्पर्क कर इस आयोजन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा।

इसमें हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद एवं प्रमुख निर्यातक तथा निर्यातक संगठन भी वांछित सहयोग करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस व्यापार मेले के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न उद्यमियों एवं निर्यातकों से सुझाव आमंत्रित कर उन्हें अमल में लाया जाएगा।

स्थानीय निर्यातक सहित अन्य उद्यमी भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव भागीदारी का निर्वाह करेंगे।

एक्सपो से विशेष रूप से संभाग के उन कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिन्हें गांव-गांव में काम करके अपने उत्पादों को बेचने के लिए दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों में जाना पड़ता है।

- **ग्रेटर नगर निगम, जयपुर में घर-घर कचरा संग्रहण पर शुल्क लागू किया; इसकी शुरूआत फरवरी, 2023 से जयपुर के दो जोन मालवीय नगर व मुरलीपुरा से होगी—**

ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने फरवरी 2023 से घर-घर कचरा संग्रहण पर शुल्क लागू किया है। इसे फिलहाल मुरलीपुरा व मालवीय नगर जोन में लागू किया गया है। इसमें शुल्क ऑनलाइन भुगतान के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसकी शुरुआत 15 फरवरी, 2023 से किया जाना प्रस्तावित है।

कचरा संग्रहण हेतु निर्धारित किया गया शुल्क - (प्रतिमाह)

घरेलू पर शुल्क		
50 वर्ग मीटर से छोटे घर पर	-	20 रुपए
300 वर्ग मीटर तक	-	80 रुपए
300 वर्ग मीटर से अधिक	-	150 रुपए
व्यावसायिक पर शुल्क		
शॉप, स्वीट स्टॉल, कॉफी हाउस	-	250 रुपए
गेस्ट हाउस, हॉस्टल	-	750 रुपए
होटल रेस्टोरेंट पर		
होटल रेस्टोरेंट	-	750 रुपए
थ्री स्टार होटल	-	1500 रुपए
थ्री स्टार व इससे अधिक	-	3000 रुपए
विवाह स्थल		
3000 वर्ग मीटर से कम	-	2000 रुपए
3000 वर्ग मीटर से ज्यादा	-	5000 रुपए
अस्पताल		
50 बेड क्षमता से कम	-	2000 रुपए
50 बेड क्षमता से अधिक	-	4000 रुपए

News Paper of 31 January, 2023

- **राजस्थान में बाल विवाह के ग्राफ में 40% कमी—**

हाल ही में जारी 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) की रिपोर्ट में राज्य में पिछले 15 वर्षों में बाल विवाहों की संख्या में 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। बाल विवाह के आंकड़ों में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान 11 प्रतिशत कमी आई है।

एनएफएचएस-5 (वर्ष 2019-21) के अनुसार, 20-24 वर्ष के आयु वर्ग की 24 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई, जो यह एनएफएचएस-4 (2015-16) के आंकड़ों से 11 प्रतिशत कम है। एनएफएचएस-3 (वर्ष 2005-06) की अवधि में 41 प्रतिशत बाल विवाह दर्ज हुए थे।

यह बाल विवाह के आंकड़े राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

47 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु

संजीव प्रकाशन

द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से अध्ययन कर सफलता प्राप्त करें।

प्रभात वालिया की अन्य पुस्तकें

- CET कम्प्यूटर का ज्ञान
- SSC CGL कम्प्यूटर नॉलेज
- सूचना सहायक भर्ती परीक्षा (शीघ्र प्रकाशित)
- सूचना सहायक मॉडल पेपर्स (शीघ्र प्रकाशित)

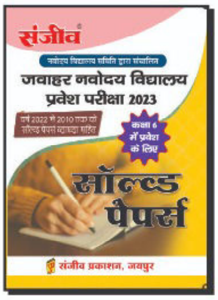

जी.सी. जाखड़ द्वारा लिखित पुस्तक

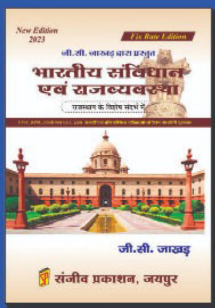

Quality Education टीम द्वारा तैयार पुस्तकें

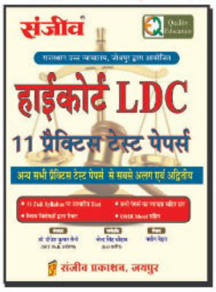

हाल ही में हुई शिक्षक ग्रेड ।। परीक्षा में अधिकांश प्रश्न संजीव प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स से

मनोहर सिंह कोटड़ा के मार्गदर्शन में तैयार पुस्तकें

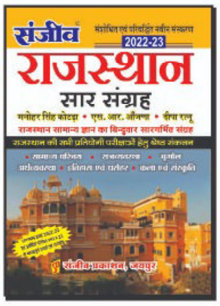

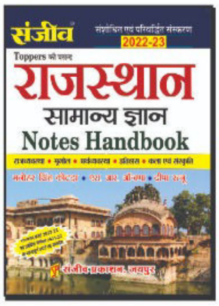

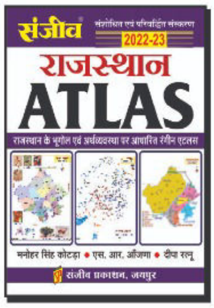

संजीव वेबसाइट से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री निःशुल्क डाउनलोड करें।
साथ ही संजीव वेबसाइट से आप E-Book भी खरीद सकतें हैं।

प्रकाशक–संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com

SHAKUN